**कार्यालय मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।**

पत्रांकः– 2170/11–सी–FP/UP/MIN/24551/2017, लखनऊ, दिनांकः जनवरी 22 ,2026

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अनपरा रेंज अंतर्गत नॉर्दन कोल फील्ड्स लि0 की बीना परियोजना को बीना ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 30.5 हे0 आरक्षित वनभूमि का 30 वर्षों के लीज पर हस्तान्तरण किये जाने एवं बाधक 14000 वृक्षों के पातन के संबंध में।

संदर्भः– भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यू0पी0/05/34/2022/एफ0सी0/991, दिनांक 29.03.2023 एवं मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर का पत्रांक–2467/33, दिनांक 04.01.2026

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्तियों का निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के उपरोक्त पत्रांक–2467/33, दिनांक 04.01.2026 द्वारा इस कार्यालय को ऑनलाइन दिनांक 21.01.2026 को अपलोड कर प्रेषित किया गया है।

अतः उपरोक्त पत्र की छायाप्रति सहित वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस अनुरोध के साथ अपलोड कर प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में **सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage-I)** निर्गत करने का कष्ट करें।

**संलग्नकः उपरोक्तानुसार।**

भवदीय,

22.01

**(ललित कुमार वर्मा)**
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

**पत्रांकः– 2170 /11–सी–FP/UP/MIN/24551/2017, दिनांकित।**

प्रतिलिपिः– प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

**संलग्नकः उपरोक्तानुसार।**

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट।
3. क्षेत्रीय महाप्रबन्धक, नार्दन कोल फील्डस लि0, बीना परियोजना, बीना–सोनभद्र।

22.01

**(ललित कुमार वर्मा)**
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

2100
11-सी
16/01/2026

# कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

**पत्रांक–2467 / मी0क्षे0 / 33, मीरजापुर, दिनांक ~~दिसम्बर~~ 04-01 ~~2025~~ 2026**

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषयः– जनपद सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग के अनपरा रेंज अन्तर्गत नार्दन कोल फील्ड् लि0 की बीना परियोजना को बीना–ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 30.50 हे0 आरक्षित वनभूमि का 30 वर्षो के लीज पर हस्तान्तरण किये जाने एवं बाधक 14000 वृक्षो के पातन के समबन्ध में।

संदर्भः–
1–भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर एच0 अलीगंज, लखनऊ का पत्र संख्या–8बी / यू0पी0 / 05 / 34 / 2022 / एफ.सी. / 991, दिनांक 29.03.2023
2–मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक–3150 / 11–सी–FP/UP/Min /24551/2017, दिनांक–31.03.2023
3–मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक–621 / 11–सी–FP/UP/Min /24551/2017, दिनांक–20.08.2025

Adso
14.1
APCCF/Nodal
14/1/26

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक 29.03.2023 द्वारा दो बिन्दुओ पर सूचना / अभिलेख उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी। उक्त के अनुपालन में वांछित सूचना / अभिलेख प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट ने अपने कार्यालय पत्रांक–2214 / रेनुकूट / 15–108, दिनांक 24.12.2025 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट द्वारा प्रेषित सूचना एतद्सह संलग्नकर सूचनार्थ एवं आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय
4.1.2026
(सुशान्त शर्मा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

संख्या– / अ / समदिनांक।

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग को उनके पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सुशान्त शर्मा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट(सोनभद्र)

पत्रांक– १२१५ /रेनुकूट/ 15–108 दिनांक,रेनुकूट,दिसम्बर, २५ 2025

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

विषयः– जनपद–सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अनपरा रेंज अन्तर्गत नार्दन कोल फील्डस लि0 की बीना परियोजना को बीना–ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 30.60 हे0 आरक्षित वन भूमि का 30 वर्षो के लीज पर हस्तान्तरण किये जाने एवं बाधक 14000 वृक्षो के पातन की अनुमति के संबंध में ।
(ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या–**FP/UP/MIN/24551/2017**) ।

संदर्भः– 1–भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय , केन्द्रीय भवन, पंचम तल ,सेक्टर एच0 अलीगंज, लखनऊ का पत्र संख्या– 8बी/यू0पी0/05/34/2022/एफ0सी0/991 दिनांक– 29.03.2023
2–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक– 3150/11–सी– **FP/UP/MIN/24551/2017** लखनऊ दिनांक–31.03.2023
3– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक– 621/11–सी– **FP/UP/MIN/24551/2017** लखनऊ दिनांक–20.08.2025
4–क्षेत्रीय महाप्रबन्धक एन0सी0एल0 बीना परियोजना, बीना सोनभद्र का पत्रांक–बीना/पर्या./उ0प्र0/वन/2025/77 दिनांक–17.12.2025

महोदय,

विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करे । प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक– 29.03.2023 व मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक– 31.03.2023 द्वारा दो बिन्दुओ से संबंधित निम्न सूचना/अभिलेखो की मॉग की गयी :–

| क्र0 सं0 | भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय , केन्द्रीय भवन, पंचम तल ,सेक्टर एच0 अलीगंज, लखनऊ का पत्र संख्या– 8बी/यू0पी0/05/34/2022/एफ0सी0/991 दिनांक– 29.03.2023 मे अंकित बिन्दु । |
|---|---|
| 1 | No non –forest land is available in the State for raising Compensatory Afforestation . |
| 2 | No other category of forest land such as revenue lands/zudupi jungle/chhote/bade jharka jungle which is not under the management and/or administrative control of the State forest Department is available for raising Compensatory Afforestation |

उक्त दोनो बिन्दुओ से संबंधित सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु प्रभाग के विभिन्न पत्रों द्वारा एन0सी0एल0 बीना परियोजना से अनुरोध किये जाने पर क्षेत्रीय महाप्रबन्धक एन0सी0एल0 बीना परियोजना ने अपने कार्यालय के संदर्भित पत्र संख्या– बीना/पर्या./उ0प्र0/वन/2025/77 दिनांक–17.12.2025 द्वारा भारत सरकार के पत्र दिनांक– 17.03.2025 एवं 17.12.2024 की छायाप्रति संलग्न करते हुये ऑनलाइन प्रस्ताव में अपलोड किये गये 61.00 हे0 अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण किये जाने वावत् अनुरोध किया गया है।

<u>भारत सरकार के पत्र दिनांक–17.03.2025 में उल्लिखित विवरण निम्न प्रकार हैः–</u>

i. As per the provisions of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Amendment Rules, 2024, there is no requirement of certificate from the State Government certifying the non-availability of the non-forest land for the projects of Central PSU/entities and captive coal blocks of the State PSUs

ii. The provisions of the amendment Rules 2024, have further been clarified by the Central Government in its Guidelines issued on 17.12.2024 (copy enclosed). The same may be adhered to by the processing authorities in the State.

<u>भारत सरकार के पत्र दिनांक–17.12.2024 में उल्लिखित विवरण निम्न प्रकार हैः–</u>

As per the provisions of the van (sanrakshan evam samvardhan ) amendment rules 2024 project of central government entities/ CPSU and captive coal blocks of the state PSUs are eligible for raising CA over degraded forest land which will be double in extent of the forest land being diverted. accordingly, the state government/UT shall not insist for providing non-forest land as CA unless in cases wherein the central government agencies/CPSUs or state government PSUs with

Scanned by CamScanner

captive coal blocks are forthcoming to provide non-forest land available with them as CA or the state government/ UT administration is willing to provides non-forest land on such terms and condition which is agreed by the central government agencies/ CPSUs or state government PSUs in case of captive coal blocks.

भारत सरकार द्वारा जारी उक्त आदेश दिनांक– 17.12.2024 एवं 17.03.2025 के क्रम मे मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के स्तर से भारत सरकार पर्यावरण जल एवं जलवायु परिवर्तन मंत्राालय, क्षेत्रीय कार्यालय, (मध्य क्षेत्र) केन्द्रीय भवन अलीगंज लखनऊ को वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुये उचित दिशा निर्देश देने हेतु अनुरोध किया गया है, किन्तु अभी तक कोई निर्देश प्राप्त होने की सूचना प्रभाग के संज्ञान में नहीं है।

यहॉ यह उल्लेख करना है कि प्रश्नगत प्रस्ताव प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर वर्ष 2017 में ऑनलाईन अपलोड किया गया है, तब से पत्राचार में है। उक्त प्रस्ताव भारत सरकार की परियोजना होने के कारण, भारत सरकार द्वारा जारी नवीनतम आदेश दिनांक– 17.12.2024 एवं 17.03.2025 में उल्लिखित प्राविधानों के क्रम में प्रभावित वनभूमि 30.50 हे0 के दोगुने अवनत वनभूमि 61.00 हे0 पर क्षतिपूरक वनीकरण की योजना सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख जो ऑनलाइन प्रस्ताव में अपलोड किये गये है उसके आधार पर सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी किये जाने के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रयोक्ता अभिकरण के पत्र दिनांक–17.12.2025 एवं भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक–17.12.2024 एवं 17.03.2025 की छायाप्रति संलग्न करते हुये संस्तुति सहित रिपोर्ट प्रेषित है।

भवदीय

(कमल कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

संख्या– 2215 अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2–महाप्रबन्धक, नार्दन कोल फील्डस लि0 बीना, परियोजना, बीना–सोनभद्र को उनके पत्र संख्या– बीना/पर्या./उ0प्र0/वन/2025/77 दिनांक–17.12.2025 के क्रम में ।

(कमल कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

Scanned by CamScanner

कोलफील्ड्सलिमिटेड
(मिनीरत्नकंपनी)
कोलइण्डियालिमिटेडकीअनुषंगीकंपनी)

Northern Coalfields Limited
(A Miniratna Company)
(A subsidiary of Coal India Limited)

महाप्रबंधक कार्यालय / Office of the General Manager
CIN- U10102MP1985GOI003160
An ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 & ISO 45001 Certified Company
बीना परियोजना, जिला- सोनभद्र (उ.प्र.) पिन- 231220 / Post- Bina Project, Distt- Sonebhadra (U.P.)- 231220
Phone :05446-276279 (O), 267280 (R) e-mail :cgmbin.ncl@coalindia.in Website :www.nclcil.in

क्र: बीना/ पार्य./उ०प०/ वन/ 2025/77 दिनांक: 17.12.2025

सेवा में,
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनूकूट वन प्रभाग,
उ०प० वन विभाग

**विषय:- जनपद - सोनभद्र में रेनूकूट वन प्रभाग के अनपरा रेंज अंतर्गत नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लि० की बीना परियोजना को बीना ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 30.5 हे० आरक्षित वन भूमि के लिए 61 हे० degraded** वन क्षेत्र में प्रस्तावित CA स्कीम को सहमति प्रदान करने बावत्।

संदर्भ:- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्र दिनांक: 17.12.2024; व 17.03.2025

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी पत्रांक 17.03.2025 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें:

i. *As per the provisions of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Amendment Rules, 2024, there is no requirement of certificate from the State Government certifying the non-availability of the non-forest land for the projects of Central PSU/entities and captive coal blocks of the State PSUs.*
ii. *The provisions of the amendment Rules 2024, have further been clarified by the Central Government in its Guidelines issued on 17.12.2024 (copy enclosed). The same may be adhered to by the processing authorities in the State.*

इसके अतिरिक्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र दिनांक 17.12.2024 (प्रति संलग्न) के बिन्दु क्र० - (iv) का भी अवलोकन करने का कष्ट करें:

*"As per the provisions of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Amendment Rules, 2024, projects **of Central Government entities/CPSU** and captive coal blocks of the State PSUs are eligible for raising **CA over degraded forest land which will be double in extent of the forest land being diverted**. Accordingly, the State **Government/UT shall not insist for providing non-forest land as CA** unless in cases wherein the Central Government Agencies/CPSUs or State Government PSUs with*

Scanned by CamScanner

*captive coal blocks are forthcoming to provide non-forest land available with them as CA or the State Government/UT Administration is willing to provides non-forest land on such terms and condition which is agreed by the Central Government Agencies/CPSUs or State Government PSUs in case of captive coal blocks."*

उपरोक्त पत्रों से यह स्पष्ट है कि Central Public Sector Undertakings के लिए गैर-वन भूमि की अनुपलब्धता को प्रमाणित करने हेतु राज्य सरकार से प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है एवं Central Public Sector Undertakings के लिए दोगुने अवक्रमित वन भूमि (double degraded forest) क्षेत्र में प्रतिपूरक वनीकरण (Compensatory Afforestation) करवाने का प्रावधान उपलब्ध है।

उपरोक्त पत्र से यह भी स्पष्ट है कि राज्य में प्रसंस्करण प्राधिकारियों द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की गाइडलाइन्स दिनांक: 17.12.2024 का पालन किया जा सकता है।

एन०सी०एल० एक Central PSU है तथा इस प्रस्ताव (FP/UP/MIN/24551/2017) हेतु बीना परियोजना के लिए 61 हे० degraded वन क्षेत्र में प्रस्तावित CA स्कीम उपलब्ध है जो कि पूर्व में भारत सरकार प्रेषित कि गयी थी।

अतः आपसे अनुरोध है कि बीना ककरी एकीकरण परियोजना में 61 हे० degraded वन क्षेत्र में प्रस्तावित CA स्कीम को सहमति प्रदान करने हेतु अग्रेतर कार्यवाही करने कि कृपा करें ।

सधन्यवाद

भवदीय

17.12.24

क्षेत्रीय महाप्रबंधक,
बीना परियोजना, एन०सी०एल०

प्रतिलिपि: महाप्रबंधक (पर्या०/ वन), एन०सी०एल०, सिंगरौली।

Scanned by CamScanner

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Forest Conservation Division)

Indira Paryavaran Bhawan,
Aliganj, Jor Bagh Road,
New Delhi: 110003
Dated: March, 2025

To

The Principal Secretary (Forests),
Government of Maharashtra,
Manrtalaya Mumbai

**Sub: Permitting double the degraded forest land in lieu of non-forest land for certain projects taken up by CPSU / SPSU and other government agencies - reg.**

Madam/Sir,

I am directed to refer to the State Government of Maharashtra's letter no. FLD-2025/CR-42/F-10 dated 25.02.2025 on the above subject seeking advise from the Ministry on the implementation of the Guidelines related to compensatory afforestation vis-à-vis directions passed by the Hon'ble Supreme Court in its order dated 3.02.2025. In this connection, it is to inform that after examination of the concerns of the State Government, the following is informed:

i. As per the provisions of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Amendment Rules, 2024, there is no requirement of certificate from the State Government certifying the non-availability of the non-forest land for the projects of Central PSU/entities and captive coal blocks of the State PSUs.
ii. The provisions of the amendment Rules 2024, have further been clarified by the Central Government in its Guidelines issued on 17.12.2024 (copy enclosed). The same may be adhered to by the processing authorities in the State.
iii. In light of directions contained in the Hon'ble Supreme Court's order dated 3.02.2025 and 4.03.2025, it is further to inform that no forest land should be diverted without compensatory afforestation for which land is to provided in accordance with relevant provisions provided under the Van (Sanrakhan Evam Samvardhan) Rules, 2023 (as amended) and Guidelines issued thereunder.

This issues with the approval of the competent authority.

Digitally signed by
CHARAN JEET SINGH
Date: 17-03-2025
09:33:49

Yours faithfully,

**(Charan Jeet Singh)**
Scientist 'E'

Copy to:

1. Principal Chief Conservator of Forests & HoFF, State Government of Maharashtra, Nagpur
2. Dy Director General of Forests (Central), Regional Offices of the MoEF&CC at Nagpur
3. Nodal Officer (Sanrakshan Evam Samvardhan), O/o the PCCF, State

Scanned by CamScanner

Government of Maharashtra, Nagpur

4. Guard File.

Scanned by CamScanner

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Forest Conservation Division)

Indira Paryavaran Bhawan,
Aliganj, Jor Bagh Road,
New Delhi: 110003
Dated: December, 2024

To

The Addl. Chief Secretaries of Forests/Principal Secretary (Forests),
All States Governments and Union territory Administrations

**Sub: Streamlining of the approval process with regards to compensatory afforestation as envisaged in the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 as amended on 20.09.2024 – reg.**

**Madam/Sir,**

I am directed to refer to the above subject and toinform that based on the references received from the Ministry of Mines, and Ministry of Coal, the provisions related to raising of compensatory afforestation, as envisaged in the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 as amended on 20.09.2024, have been reviewed by the Ministry and after due deliberations, the Central Government, in accordance with the provisions of section 3C of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 hereby issues the following clarifications:

i. Provisions of Rule 14(1) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023, provides that the non-forest land identified for raising Compensatory Afforestation (CA) is to be notified as Protected Forests before final approval (Stage-II) approval is granted by the Central Government. However, in cases where non-forest land identified for CA has been transferred and mutated in favour of the State Forest Department (SFD), the Central Government may accord final approval keeping in view the fact that provisions of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 become applicable on such lands being entered as forest in government record/record of rights.

ii. In such cases, referred in para (i) above, the non-forest land forest land proposed for CA, shall be notified as Protected Forest under section 29 of the Indian Forest Act, 1927 of local forest Act before handing over of forest land to the User Agency by the State Government. The Nodal Officer, after notification of such non-forest lands, shall upload a copy of said notification on the PARIVESH portal.

iii. For the purpose of rule 13(4)(a) of the States or Union territory Administrations, having forest area more than 33% of their total geographical area, concerned State Government/UT Administrationmay authorise a suitable officer to issue certificate of non-availability of the suitable non-forest land for raising CA.

iv. As per the provisions of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Amendment Rules, 2024, projects of Central Government entities/CPSU and captive coal blocks of the State PSUs are eligible for raising CA over degraded forest land which will be double in extent of the forest land being diverted. Accordingly, the State Government/UT shall not insist for providing non-forest land as CA unless in cases wherein the Central Government

Scanned by CamScanner

Agencies/CPSUs or State Government PSUs with captive coal blocks are forthcoming to provide non-forest land available with them as CA or the State Government/UT Administration is willing to provides non-forest land on such terms and condition which is agreed by the Central Government Agencies/CPSUs or State Government PSUs in case of captive coal blocks.

v. With regards to the applicability of the provisions of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Amendment Rules, 2024 in respect of proposals of the Central Agencies/PSUs and captive coal blocks of the State PSUs which were granted 'in-principle' approval stipulating CA over non-forest land, the following clarification is given in this regard:

   a. Proposals, which were submitted by the States/UTs before notification of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Amendment Rules, 2024, along with the proposal of raising CA over degraded forest land (DFL) and were granted 'in-principle' approval stipulating CA over non-forest land (NFL), shall be allowed to submit compliance of 'in-principle' approval along with CA proposal over DFL in lieu of NFL. The Central Government will consider and grant final approval in such cases stipulating CA over DFL.

   b. Proposals, which were submitted by the States/UTs along with CA proposal over non-forest land and were granted 'in-principle' approval stipulating CA over non-forest land (NFL), can also be allowed to submit compliance of 'in-principle' approval along with CA proposal over DFL provided the non-forest land proposed for CA is not transferred and mutated in favour of the State Forest Department. In such cases, the Central Government or its Regional Office, based on the request of the State/UT Government or user agency, shall amend the condition of in-principle approval to raise CA over DFL on a case to case basis and subsequently the User Agency shall submit the compliance of in-principle for the obtaining the 'final' approval.

In view of the above, the State Government and Union territory Administrations are requested to take into consideration the guidelines mentioned hereinabove while considering the proposals submitted under section 2 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980.

This issues with the approval of the competent authority.

Yours faithfully,

Signed by
Charan Jeet Singh
Date: 17-12-2024 13:56:41

**(Charan Jeet Singh)**
Scientist 'E'

Copy to:

1. Director, PMO, South Block, New Delhi
2. Secretary, Ministry of Mines /Coal /Steel/ Power/ Railways/ MoRT&H/ Defence/MHA
3. Secretary, Ministry of Defence, Government of India
4. Principal Chief Conservator of Forests & HoFF, All States Governments and Union territory Administrations
5. Dy Director General of Forests (Central) All Regional Offices of the MoEF&CC

Scanned by CamScanner

6. Nodal Officers, dealing with the matters related to the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980, All States Governments and Union territory Administrations
7. Head, NIC, MoEFCC for aligning the PARIVESH 2.0 as per above

Scanned by CamScanner